[2012] 6 एससीआर 710

मुकुट बिहारी और अन्य

बनाम

राजस्थान राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 870/2012)

25 मई, 2012

[न्यायमूर्ति, डॉ. बी.एस. चौहान और न्यायमूर्ति, दीपक मिश्रा]

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988:

धारा 7 और 13(1) (डी) सपठित धारा 13(2) – धारा 120 बी आईपीसी के तहत अभियोजन – रिश्वत की मांग और स्वीकृति – जाल – दागी धन की जब्ती – विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि और 2 साल की सजा आरआई – दोषसिद्धि और सजा उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई – अपील पर, माना गया: दोषसिद्धि उचित है – मांग के साथ–साथ रिश्वत की स्वीकृति पर्याप्त रूप से साबित हुई – स्वतंत्र गवाहों सहित अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों से जाल साबित हुआ – इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी की सजा घटाकर 1 वर्ष कर दी गई उनकी सेवाएँ खो गईं; कि मामला दो दशक पुराना था; कि आरोपी गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे और आरोपी पहले ही छह महीने की कैद काट चुके थे – दंड संहिता, 1860 – धारा 120B –

अनुभाग। 7, 13 और 20 – अधिनियम के तहत अपराध का गठन करने के लिए अवैध संतुष्टि की मांग अनिवार्य है – केवल राशि की प्राप्ति अपराध को ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं है, मांग के संबंध में किसी भी सबूत के अभाव में और राशि को अवैध मानने की स्वीकृति परितोष – भार जिस पर पड़ता है। आरोपी ने प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य के माध्यम से धारा 20 के तहत उठाए गए वैधानिक अनुमान को विस्थापित करने के लिए कहा कि धन को अधिनियम की धारा 7 में संदर्भित किसी मकसद या इनाम के अलावा अन्य रूप में स्वीकार किया गया था – अदालत को आरोपी के स्पष्टीकरण पर विचार करना आवश्यक है । संभाव्यता की प्रधानता की कसौटी पर न कि सभी उचित संदेहों से परे प्रमाण की कसौटी पर – साक्ष्य अनुमान।

आपराधिक मुकदमा – रिश्वत का मामला – किसी अन्य गवाह द्वारा शिकायतकर्ता के बयान की पुष्टि की आवश्यकता – अभिनिर्धारित किया गया: *एक ट्रैप पार्टी में एक छाया गवाह वांछनीय है , लेकिन इसकी मात्र अनुपस्थिति पूरी ट्रैप कार्यवाही को ख़राब नहीं करेगी – साक्ष्य।*

अपीलकर्ता–अभियुक्तों पर धारा 7 के तहत मुकदमा चलाया गया और अपीलकर्ता–अभियुक्तों पर धारा 7 के तहत मुकदमा चलाया गया और यह था कि पीडब्लू–1 ने आरोपी अपीलकर्ता नंबर 1 के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी कि उसने रुपये की मांग की थी । उसके (शिकायतकर्ता के) पिता के लिए डिस्चार्ज टिकट जारी करने के लिए 100/– की रिश्वत ली, क्योंकि उन्हें उस अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी जिसमें अपीलकर्ता–अभियुक्त कर्मचारी थे। एक जाल की व्यवस्था की गई, जिसके तहत शिकायतकर्ता अपीलकर्ता नंबर 1 से मिला और उसके साथ बातचीत की, और उसके बाद शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ता नंबर 1 के कहने पर दागी रकम अपीलकर्ता नंबर 2 को सौंप दी। ट्रैप पार्टी ने दोनों अपीलकर्ताओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया और उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की।

इस न्यायालय में अपील में अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध का गठन करने के लिए, अभियोजन पक्ष को अवैध परितोषण की मांग को साबित करना होगा; कि दूषित धन की वसूली या उसकी स्वीकृति मात्र आपराधिक दायित्व तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है; कि जाल को एक स्वतंत्र चश्मदीद द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए; उस इच्छुक गवाह की पुष्टि की जानी चाहिए; कि शिकायतकर्ता और अभियुक्त के बीच की बातचीत पंच गवाह द्वारा सुनी जानी चाहिए थी; और यह कि यदि दो विचार संभव हैं, तो अभियुक्त के पक्ष में जो विचार हो उसे प्रबल होना चाहिए।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

अभिनिर्धारित: 1.1 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराध का गठन करने के लिए अवैध परितोषण की मांग अनिवार्य है। केवल दागी धन की वसूली आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब मामले में ठोस सबूत विश्वसनीय नहीं है, जब तक कि वहां न हो। रिश्वत के भुगतान को साबित करने या यह दिखाने के लिए सबूत है कि पैसा स्वेच्छा से रिश्वत के रूप में लिया गया था। अवैध परितुष्टि के रूप में राशि की मांग और स्वीकृति के संबंध में किसी भी सबूत के अभाव में, आरोपी द्वारा राशि की प्राप्ति मात्र अपराध को मजबूत करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन धारा 20 के तहत उठाए गए वैधानिक अनुमान को विस्थापित करने का बोझ आरोपी पर होता है। अधिनियम की धारा 7 में उल्लिखित उद्देश्य या इनाम के अलावा, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य सबूतों को रिकॉर्ड पर लाकर, उचित संभावना के साथ स्थापित करने के लिए, कि पैसा उसके द्वारा स्वीकार किया गया था। अधिनियम की धारा 20 के प्रावधानों को लागू करते समय, अदालत को अभियुक्त द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर केवल संभाव्यता की प्रबलता की कसौटी पर विचार करना आवश्यक है, न कि सभी उचित संदेह से परे सबूत की कसौटी पर। हालाँकि, इससे पहले कि अभियुक्त को यह बताने के लिए बुलाया जाए कि उसके पास विचाराधीन राशि कैसे पाई गई, अभियोजन पक्ष द्वारा मूलभूत तथ्य स्थापित किए जाने चाहिए। शिकायतकर्ता एक इच्छुक और पक्षपातपूर्ण गवाह है जो जाल की सफलता से चिंतित है और उसके साक्ष्य का परीक्षण उसी तरह किया जाना चाहिए जैसे किसी अन्य इच्छुक गवाह का और उचित मामले में, अदालत आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराने से पहले स्वतंत्र पुष्टि की तलाश कर सकती है। . [पैरा 8]

राम प्रकाश अरोड़ा बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1973 एससी 498; *सूरजमा / बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन)* एआईआर 1979 एससी 1408; *टी. सुब्रमण्यम । टीएन राज्य* एआईआर 2006 एससी 836:2006 (1) एससीआर 180; *ए. सुबैरव . केरल राज्य* (2009) 6 एससीसी 587; *महाराष्ट्र राज्य बनाम ओन्यानेश्वर लक्ष्मण राव वानखेड़े* (2009) 15 सेकंड 200: 2009 (11) एससीआर 513; *सीएम गिरीश बाबू बनाम सीबीआई, कोचीन, केरा उच्च न्यायालय /* एआईआर 2009 एससी 2022: 2009 (2) एससीआर 1021; *केरा /ए और अन्य राज्य । वी. जीपी. राव* (2011) 6 एससीसी 450: 2011 (6) एससीआर 864 – संदर्भित।

1.2 वर्तमान मामले में, तथ्यों की समवर्ती खोज है कि अपीलकर्ता नंबर 1 ने रिश्वत मांगी, जैसा कि पीडब्लू.1 द्वारा बताया गया है। इसे ट्रैप पार्टी के नेता, SHO (PW.10) द्वारा विधिवत समर्थन किया गया है क्योंकि उन्होंने गवाही दी थी कि वहां बैठे व्यक्तियों ने पैसे मांगे थे। स्वीकृति की विधिवत पुष्टि पीडब्लू.3 द्वारा की गई थी, जिसने बताया था कि पैसा मेज पर पड़ा हुआ था। कांस्टेबल (पीडब्लू.7) ने कहा कि उसने अपीलकर्ता नंबर 2 को पैसे गिनते हुए देखा। PW.1, PW.3, PW.6, PW.7 और PW.10 के बयानों से जाल साबित हुआ। सभी गवाहों ने पूरी तरह से बताया कि शुरू से लेकर जब्ती मेमो आदि बनाने सहित दागी धन की जब्ती तक कैसे जाल बिछाया गया था। पीडब्लू.5 ने मरीजों द्वारा दान की प्रथा को स्वीकार किया। PW.3 और PW.6 स्वतंत्र गवाह थे। [पैरा 6]

1.3 यह दलील कि शिकायतकर्ता के बयान को सभी परिस्थितियों में पुष्टि की आवश्यकता है, संक्षेप में, रिश्वत लेने वाले को गोपनीयता में अवैध संतुष्टि प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगी और फिर अभियोजन के मामले में पुष्टि के लिए जोर देगी। कानून ऐसी स्थिति का सामना नहीं कर सकता. इस प्रकार, यह आवश्यक नहीं है कि एक विश्वसनीय गवाह के साक्ष्य की पुष्टि किसी अन्य गवाह द्वारा की जाए, क्योंकि ऐसे साक्ष्य की पुष्टि रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सामग्री से होती है। इसलिए, ट्रैप पार्टी में एक छाया गवाह का होना हमेशा वांछनीय होता है, लेकिन ऐसे गवाह की अनुपस्थिति मात्र से पूरी ट्रैप कार्यवाही ख़राब नहीं हो जाएगी। [पैरा 10 और 14]

पनालाल दामोदर राठी बनाम महाराष्ट्र राज्य एआईआर 1979 एससी 1191; *श्रीमती मीना बा/वंत हेमके बनाम महाराष्ट्र राज्य* एआईआर 2000 एससी 3377: 2000 (3) एससीआर 12; *मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद और अन्य । वी .* जी. *रत्नम और अन्य ।* एआईआर 2007 एससी 2976: 2007

(9) एससीआर 259; *मणिशंकर बनाम भारत संघ और अन्य ।* (2008) 3 एससीसी 484:2008 (3) एससीआर 871 • संदर्भित।

1.4 वर्तमान मामले में, गवाहों के बयान में कोई विरोधाभास नहीं है। गवाहों ने सच कहा है कि उन्होंने अभियुक्त और शिकायतकर्ता के बीच की बातचीत नहीं सुनी। अतः उनका संस्करण बिना किसी अलंकरण एवं सुधार के है। मामले में अपीलकर्ताओं को झूठा फंसाने के लिए PW.1 के पास कोई कारण/मकसद नहीं हो सकता है । [पैरा 15)

1.5 नीचे की अदालतों ने तथ्यों पर ठीक से विचार किया और सही परिप्रेक्ष्य में सबूतों की सराहना की और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप पूरी तरह से साबित हुए। अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण कि उन्हें दुश्मनी के कारण झूठा फंसाया गया था, इस कारण से साबित नहीं किया जा सका कि शिकायतकर्ता और अपीलकर्ताओं के बीच किसी भी पिछली दुश्मनी को इंगित करने वाला कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाया जा सका और न ही यह दिखाने के लिए कोई सबूत उपलब्ध था कि शिकायतकर्ता अपने पिता को दिए गए इलाज से संतुष्ट नहीं था और वह अपीलकर्ताओं को झूठा फंसाने के लिए किसी अप्रत्यक्ष उद्देश्य से कार्य कर सकता था। इस प्रकार, दान की आड़ में, उसने अपीलकर्ताओं को दूषित धन की पेशकश की और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। [पैरा 7)

सीएम शर्मा बनाम एपी राज्य थ. एल.पी. एआईआर 2011 एससी 608: 2010 एससीआर 1105 – पर भरोसा किया गया।

2. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घटना लगभग दो दशक पहले हुई थी और अपीलकर्ता गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्होंने बहुत पहले अपनी सेवा खो दी है और लंबी मुकदमेबाजी की पीड़ा झेली है, अपीलकर्ता नंबर 1 तीव्र अग्नाशयशोथ से पीड़ित है और दोनों अपीलकर्ताओं ने छह महीने से अधिक समय तक सजा काट ली है, उनकी सजा को घटाकर एक वर्ष कर दिया गया है। [पैरा 15]

केस कानून संदर्भ:

एआईआर 1973 एससी 498 पैरा 8 में संदर्भित

एआईआर 1979 एससी 1191 पैरा 8 में संदर्भित

एआईआर 1979 एससी 1408 पैरा 8 और 10 का संदर्भ दिया गया

2000 (3) एससीआर 12 पैरा 8 और 10 का संदर्भ दिया गया

2006 (1) एससीआर 180 पैरा 8 में संदर्भित

2009 (11) एससीआर 513 पैरा 8 में संदर्भित

2009 (2) एससीआर 1021 पैरा 8 में संदर्भित

2011 (6) एससीआर 864 पैरा 8 में संदर्भित

2010 एससीआर 1105 पैरा 9 पर निर्भर है

2007 (9) एससीआर 259 पैरा 12 को संदर्भित

2008 (3) एससीआर 871 पैरा 13 को संदर्भित

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2012 की आपराधिक अपील संख्या 870।

2001 की एसबी आपराधिक अपील संख्या 726 में राजस्थान के उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के निर्णय और आदेश दिनांक 12.10.2011 से।

अपीलकर्ताओं की ओर से शोभा , राघव पांडे।

कुणाल प्रतिवादी की ओर से वर्मा , इरशाद अहमद।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

न्यायमूर्ति, डॉ. बी.एस. चौहान

1. यह अपील 2001 की एस.बी. आपराधिक अपील संख्या 726 में राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर बेंच) द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 12.10.2011 के खिलाफ दायर की गई है, जिसके द्वारा इसने विचारण न्यायालय के फैसले और आदेश की पुष्टि की है दिनांक 7.9.2001 को विशेष न्यायाधीश (एसीडी मामले), जयपुर द्वारा 1995 के नियमित विशेष आपराधिक मामले संख्या 26 (राजस्थान राज्य बनाम मुकुट) में पारित किया गया बिहारी आदि) जिससे अपीलकर्ता मुकुट बिहारी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (इसके बाद इसे "अधिनियम 1988" कहा जाएगा) की धारा 7 और 13(1)(डी) के साथ पठित धारा 13(2) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। , 1860 इसके बाद इसे 'आईपीसी' कहा जाएगा) और प्रत्येक मामले के लिए 2 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा दी गई है ; जबकि अपीलकर्ता कल्याण मल को अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(डी) के साथ पठित धारा 13(2) और धारा 120 बी आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और 2 वर्ष की अवधि तक कठोर कारावास की सजा भी दी गई है।

2. इस मामले को जन्म देने वाले तथ्य और परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं:

ए. रफीक (पीडब्लू.1) ने 16.11.1994 को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग (इसके बाद इसे "एसीडी"), टोंक के समक्ष शिकायत दर्ज कराई कि उसके पिता दीन मो . (पीडब्लू.8) ने 24.10.1994 से 12.11.1994 तक मूत्र संक्रमण के लिए सहादत अस्पताल, टोंक में इलाज कराया । उन्हें 12.11.1994 को

छुट्टी दे दी गई, हालांकि उन्हें छुट्टी टिकट जारी नहीं किया गया और जिसके लिए मुकुट बिहारी –आरोपी ने इसे जारी करने के लिए 100/– रुपये रिश्वत की मांग की। उक्त मांग 14.11.1994 को की गई थी जब शिकायतकर्ता (पीडब्लू.1) ने 75/– रुपये और 2 किलोग्राम लड्डू की पेशकश की थी ।

बी. उपरोक्त शिकायत के मद्देनजर, एक जाल की व्यवस्था की गई और योजना के अनुसार, शिकायतकर्ता की मुलाकात मुकुट से हुई अस्पताल के सर्जिकल वार्ड के स्टाफ रूम में अपीलकर्ता बिहारी से बातचीत की। वे दोनों स्टोर रूम में गए जहां शिकायतकर्ता ने मुकुट के कहने पर अपीलकर्ता कल्याण मल को 100/– रुपये दिए। –बिहारी , अपीलकर्ता। ट्रैप पार्टी ने दोनों अपीलकर्ताओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी करने के बाद दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया. मुकदमे के दौरान, बड़ी संख्या में गवाहों से पूछताछ की गई और मुकदमे के समापन पर, अदालत ने उन्हें दोषी पाया और दिनांक 7.9.2001 के फैसले और आदेश के अनुसार सजा दी।

सी. व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष 2001 की आपराधिक अपील संख्या 726 दायर की, जिसे दिनांक 12.10.2011 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

इसलिए, यह अपील.

3. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री शोभा ने प्रस्तुत किया है कि अधिनियम 1988 के तहत अपराध गठित करने के लिए , अभियोजन पक्ष को अवैध परितोषण की मांग को साबित करना होगा। दूषित धन की वसूली या उसकी स्वीकृति मात्र आपराधिक दायित्व तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि धन स्वेच्छा से दिया जा सकता है और आरोपी धन की प्राप्ति के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है। ट्रैप केस का समर्थन एक स्वतंत्र चश्मदीद गवाह द्वारा किया जाना चाहिए। इच्छुक गवाह के बयान के लिए पुष्टि की आवश्यकता होती है। पैसे की मांग और स्वीकार करते समय आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच की बातचीत को पंच गवाह द्वारा सुना/रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। यदि दो विचार संभव हों तो अभियुक्त के पक्ष में जो विचार हो उसे प्रबल होना चाहिए। तत्कालीन मामले में अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे मूलभूत तथ्य साबित करने में विफल रहा। अत: अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

4. इसके विपरीत श्री कुणाल राजस्थान राज्य के विद्वान वकील वर्मा ने अपील का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि दूषित धन स्वीकार करना अधिनियम 1988 के तहत दंडनीय अपराधों की सजा के लिए पर्याप्त सबूत है । ट्रैप मामलों में यह आवश्यक नहीं है कि कोई छाया हो शिकायतकर्ता और अभियुक्त के बीच गवाही और बातचीत को स्वतंत्र गवाह द्वारा रिकॉर्ड या सुना जाना चाहिए। छाया गवाह की अनुपस्थिति में, किसी भी कारण से, आरोपी इस बात पर जोर नहीं दे सकता है कि मांग और स्वीकृति को संपुष्टि द्वारा साबित करने के लिए कानून द्वारा आवश्यक है। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता सं. 2 ने अपीलकर्ता क्रमांक 2 के कहने पर और उसकी उपस्थिति में पैसे स्वीकार कर लिए हैं। 1. शिकायतकर्ता की गवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है और न ही दागी रकम की बरामदगी पर संदेह किया जा सकता है। इस प्रकार, अपील में योग्यता नहीं है और यह खारिज किये जाने योग्य है।

5. हमने पक्षों के विद्वान वकील द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

6. अपीलार्थी मुकुट के तथ्यों की समवर्ती खोज है जैसा कि रफीक (पीडब्लू. 1) ने कहा था, बिहारी ने रिश्वत मांगी । ट्रैप पार्टी के नेता , केशर सिंह, SHO (PW. 10) ने इसका विधिवत समर्थन किया है क्योंकि उन्होंने बताया कि वहां बैठे व्यक्तियों ने पैसे मांगे थे। स्वीकृति की विधिवत पुष्टि आरसी पारीक (पीडब्लू. 3) ने की थी , जिन्होंने बताया था कि पैसा मेज पर पड़ा था। ज़हीर अहमद, कांस्टेबल (पीडब्लू. 7) ने कहा कि उसने कल्याण मल को पैसे गिनते हुए देखा था। रफीक (पीडब्लू. 1) , आरसी पारीक (पी.डब्लू. 3) , मोहम्मद के

बयानों से जाल साबित हुआ । रशीद (पीडब्लू. 6) , जहीर अहमद (पीडब्लू. 7) और केशर सिंह (पीडब्लू. 10)। सभी गवाहों ने पूरी तरह से बताया कि जाल की शुरुआत से लेकर जब्ती मेमो आदि बनाने सहित दागी धन की जब्ती तक कैसे जाल बिछाया गया था। डॉ. बावेल (पीडब्लू. 5) ने मरीजों द्वारा दान देने की प्रथा को स्वीकार किया। श्री आरसी पारीक (पीडब्ल्यू 3) और मो . रशीद (पीडब्लू. 6) स्वतंत्र गवाह रहे हैं।

7. नीचे दी गई अदालतों ने तथ्यों पर ठीक से विचार किया और सही परिप्रेक्ष्य में सबूतों की सराहना की और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप पूरी तरह से साबित हुए। अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण कि उन्हें दुश्मनी के कारण झूठा फंसाया गया था, इस कारण से साबित नहीं किया जा सका कि शिकायतकर्ता और अपीलकर्ताओं के बीच किसी भी पिछली दुश्मनी को इंगित करने वाला कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाया जा सका और न ही यह दिखाने के लिए कोई सबूत उपलब्ध था कि शिकायतकर्ता अपने पिता को दिए गए इलाज से संतुष्ट नहीं था और वह अपीलकर्ताओं को झूठा फंसाने के लिए किसी अप्रत्यक्ष उद्देश्य से कार्य कर सकता था। इस प्रकार, दान की आड़ में, उसने अपीलकर्ताओं को दूषित धन की पेशकश की और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया।

8. इस मुद्दे पर कानून अच्छी तरह से तय है कि अधिनियम 1988 के तहत अपराध का गठन करने के लिए अवैध संतुष्टि की मांग अनिवार्य है । केवल दागी धन की वसूली आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब मामले में ठोस सबूत नहीं है विश्वसनीय, जब तक कि रिश्वत के भुगतान को साबित करने या यह दिखाने के लिए सबूत न हो कि पैसा स्वेच्छा से रिश्वत के रूप में लिया गया था। अवैध परितुष्टि के रूप में राशि की मांग और स्वीकृति के संबंध में किसी भी सबूत के अभाव में, आरोपी द्वारा राशि की प्राप्ति मात्र अपराध को मजबूत करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन धारा 20 के तहत उठाए गए वैधानिक अनुमान को विस्थापित करने का बोझ आरोपी पर होता है। अधिनियम 1988 में, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को रिकॉर्ड पर लाकर, उचित संभावना के साथ यह स्थापित करने के लिए कि धन उसके द्वारा अधिनियम, 1988 की धारा 7 में निर्दिष्ट उद्देश्य या इनाम के अलावा, किसी अन्य रूप में स्वीकार किया गया था । अधिनियम की धारा 20 के प्रावधानों को लागू करते हुए, अदालत को अभियुक्त द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर केवल संभाव्यता की प्रबलता की कसौटी पर विचार करना आवश्यक है, न कि सभी उचित संदेह से परे सबूत की कसौटी पर। हालाँकि, इससे पहले कि अभियुक्त को यह बताने के लिए बुलाया जाए कि उसके पास विचाराधीन राशि कैसे पाई गई, अभियोजन पक्ष द्वारा मूलभूत तथ्य स्थापित किए जाने चाहिए। शिकायतकर्ता एक इच्छुक और पक्षपातपूर्ण गवाह है जो जाल की सफलता से चिंतित है और उसके साक्ष्य का परीक्षण उसी तरह किया जाना चाहिए जैसे किसी अन्य इच्छुक गवाह का और उचित मामले में अदालत आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराने से पहले स्वतंत्र पुष्टि की तलाश कर सकती है।

> (वीडियो: राम प्रकाश अरोड़ा बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1973 एससी 498 ; पनालाल दामोदर राठी बनाम महाराष्ट्र राज्य एआईआर 1979 एससी 1191 ; सूरजमल बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) एआईआर 1979 एससी 1408 ; श्रीमती मीना बलवंत हेमके बनाम महाराष्ट्र राज्य एआईआर 2000 एससी 3377 ; टी. सुब्रमण्यम बनाम टीएन राज्य, एआईआर 2006 एससी 836 ; ए. सुबैर बनाम केरल राज्य (2009) 6 एससीसी 587 ; महाराष्ट्र राज्य बनाम ज्ञानेश्वर लक्ष्मण राव वानखेड़े (2009) 15 एससीसी 200 ; सीएम गिरीश बाबू बनाम सीबीआई, कोचीन, केरल उच्च न्यायालय, एआईआर 2009 एससी 2022 ; और केरल राज्य और अन्य । वी . सीपी राव (2011) 6 एससीसी 450)

9. अपीलकर्ताओं के मामले में कोई योग्यता नहीं है क्योंकि मामला पूरी तरह से सीएम शर्मा बनाम एपी टीएच राज्य में इस न्यायालय के फैसले द्वारा कवर किया गया है। आईपी, एआईआर 2011 एससी 608 , जिसमें एक समान मुद्दा उठाया गया था कि शिकायतकर्ता छाया गवाह के साथ आरोपी के कार्यालय में गया था लेकिन आरोपी ने छाया गवाह को चैंबर से बाहर जाने के लिए कहा। छाया गवाह कक्ष से बाहर चला गया। हालाँकि, शिकायतकर्ता छाया गवाह को चैंबर में लाया और आरोपी को समझाया कि वह उसका फाइनेंसर है। इसके बावजूद आरोपी ने फिर से छाया गवाह को चैंबर से बाहर जाने के लिए कहा और इस तरह वह बाहर

चला गया। आरोपी ने पैसे की मांग की और शिकायतकर्ता ने उसे दागी रकम दे दी, जो उसने अपने दाहिने हाथ से प्राप्त की थी और पतलून की दाहिनी ओर की जेब में रखी थी। एक संकेत दिया गया था, जिस पर टीम ने उसे पकड़ लिया और आरोपी को पकड़ लिया और आरोपी के दाहिने हाथ की उंगलियों और दाहिने पतलून की जेब पर सोडियम कार्बोनेट परीक्षण किया, जो गुलाबी हो गया। दागी नोट कार्यालय के फर्श पर पड़े थे, जिन्हें रिकार्ड किया गया।

10. यह न्यायालय, पनालाल सहित इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद दामोदर राठी (सुप्रा) और श्रीमती। मीना बलवंत हेमके (सुप्रा) ने माना कि अभियुक्त की इस दलील को स्वीकार करना कि शिकायतकर्ता के संस्करण को सभी परिस्थितियों में पुष्टि की आवश्यकता है, संक्षेप में रिश्वत लेने वाले को गोपनीयता में अवैध संतुष्टि प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और फिर अभियोजन के मामले में पुष्टि के लिए जोर दिया जाएगा। कानून ऐसी स्थिति का सामना नहीं कर सकता. इस प्रकार, यह आवश्यक नहीं है कि एक विश्वसनीय गवाह के साक्ष्य की पुष्टि किसी अन्य गवाह द्वारा की जाए, क्योंकि ऐसे साक्ष्य की पुष्टि रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सामग्री से होती है। अदालत ने पनालाल के मामले को और अलग कर दिया दामोदर राठी (सुप्रा) ने इस आधार पर कहा कि उस मामले में पंच गवाह ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया था और इसलिए, आरोपी को संदेह का लाभ दिया गया था। श्रीमती में. मीना बलवंत हेमके (सुप्रा) क्योंकि साक्ष्य विरोधाभासी थे, पुष्टि आवश्यक पाई गई।

11. निस्संदेह, श्रीमती में। मीना बलवंत हेमके (सुप्रा), इस न्यायालय ने माना कि कानून हमेशा ट्रैप पार्टी में एक छाया गवाह की उपस्थिति और महत्व का पक्ष लेता है, न केवल ऐसे गवाह को देखने की सुविधा प्रदान करता है बल्कि यह भी सुनता है कि क्या होता है और कैसे होता है ।

12. यह न्यायालय मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद एवं अन्य । वी. जी. रत्नम एवं अन्य , एआईआर 2007 एससी 2976 , ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या पैरा संख्या में निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। रेलवे सतर्कता नियमावली के 704–705 से विभागीय कार्यवाही निष्प्रभावी हो जायेगी। उक्त मैनुअल में जाल के मामले में छाया गवाह की वांछनीयता/आवश्यकता के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया प्रदान की गई है। इस न्यायालय ने माना कि ये केवल कार्यकारी निर्देश और दिशानिर्देश थे और इनमें वैधानिक बल नहीं था, इसलिए, इसका पालन न करने से कार्यवाही ख़राब नहीं होगी। कार्यकारी निर्देश/आदेश किसी भी व्यक्ति को कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार प्रदान नहीं करते हैं और उन अधीनस्थ अधिकारियों पर कोई कानूनी दायित्व नहीं डालते हैं जिनके मार्गदर्शन के लिए उन्हें जारी किया जाता है।

13. मोनी शंकर बनाम भारत संघ और अन्य, (2008) 3 एससीसी 484 में इस न्यायालय ने माना कि रेलवे सतर्कता मैनुअल में निहित निर्देशों को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे झूठे निहितार्थ से बचने के लिए सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं। एक रेलवे कर्मचारी का.

14. जहां तक तत्काल मामले का सवाल है, अपीलकर्ता राजस्थान राज्य के स्वास्थ्य विभाग के तहत काम कर रहे थे। प्रासंगिक समय पर राजस्थान राज्य के स्वास्थ्य विभाग में लागू रेलवे सतर्कता नियमावली में निहित पैराग्राफ के अनुरूप कोई प्रावधान नीचे की अदालतों के ध्यान में नहीं लाया गया था, न ही हमारे सामने पेश किया गया था।

इसलिए, यह माना जा सकता है कि ट्रैप पार्टी में एक छाया गवाह का होना हमेशा वांछनीय होता है, लेकिन ऐसे गवाह की अनुपस्थिति से पूरी ट्रैप कार्यवाही ख़राब नहीं हो जाएगी।

15. मौजूदा मामले में गवाहों के बयान में कोई विरोधाभास नहीं है। गवाहों ने सच कहा है कि उन्होंने अभियुक्त और शिकायतकर्ता के बीच की बातचीत नहीं सुनी। अतः उनका संस्करण बिना किसी अलंकरण एवं सुधार के है। रफीक (पीडब्लू. 1) के पास मामले में अपीलकर्ताओं को झूठा फंसाने का कोई कारण/मकसद नहीं हो सकता है ।

अपील में कोई दम नहीं है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

हालाँकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि घटना लगभग दो दशक पहले हुई थी और अपीलकर्ता गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, वे बहुत पहले ही अपनी सेवा खो चुके हैं और लंबी मुकदमेबाजी की पीड़ा झेल चुके हैं, अपीलकर्ता नंबर 1 तीव्र अग्नाशयशोथ और दोनों से पीड़ित है। अपीलकर्ताओं ने छह महीने से अधिक समय तक सजा काट ली है, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उनकी सजा को घटाकर एक वर्ष कर दिया गया है।

अपील खारिज

सौरभ त्रिपाठी द्वारा अनुवादित